किन मूल्यों की घुट्टी पिलाना चाहते हैं एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक महोदय!

एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत इस बात से बेहद दुखी हैं कि उन पर नये स्कूली पाठ्यक्रम के जरिये शिक्षा क्षेत्र में भाजपा एजेण्डा लागू करने का आरोप लगाया जा रहा है। कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर मेरे उपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि मेरी नियुक्ति केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने की है, इसलिए मैं पार्टी लाइन पर काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरी सेवा के दौरान बार-बार विभिन्न पदों पर मेरी नियुक्तियां कांग्रेस के मंत्रियों ने की हैं। एन.सी.ई.आर.टी. में मेरी पहली नियुक्ति प्रो. नूरुल हसन ने की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझे बाल भवन का निदेशक बनाया था। फिर अर्जुन सिंह ने अपने मंत्रित्व काल में शिक्षकों की शिक्षा के लिए बनी राष्ट्रीय परिषद के निदेशक पद पर मेरी नियुक्ति का अनुमोदन किया था। उन्होंने इन हवालों से अपने ऊपर लगाये जा रहे आरोपों को निराधार बताया।

प्रो. राजपूत शिक्षा क्षेत्र के तेजतर्रार नौकरशाह हैं। जाहिर है बुद्धिमान तो होंगे ही। लेकिन, अफसोस कि उनके द्वारा अपने बचाव में दिये गये सबूत आरोपों को खारिज नहीं करते। दी गयी नजीरें सिर्फ इतना ही सिद्ध करती हैं कि उनके व्यक्तित्व का चारित्रिक गुण किसी द्रव के गुण जैसा है। वह पूंजीवादी व्यवस्था में उच्च पदासीन बहुतेरे उन लोगों में से एक हैं जो हर थाली के बैंगन होते हैं। ऐसे लोगों के सफल जीवन का सूत्रवाक्य होता है - "बहे बयार जैसी, पीठ तस कीजै"। अपनी इसी खासियत के कारण प्रो. राजपूत कांग्रेसी ब्राण्ड प्रगतिशीलों से लेकर जोशी जी की बिरादरी तक के बीच समान रूप से अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में सफल रहे हैं। प्रो. राजपूत के व्यक्तित्व की यही तरलता आज उन्हें वैसा सोचने, बोलने और करने को प्रेरित कर रही है जैसा सत्ता का मौजूदा समीकरण चाह रहा है।

समाज में मूल्यों के ह्रास पर बेहद चिन्तित प्रो. राजपूत आरोप लगाने वालों पर उलटे सवाल दागते हैं कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में मूल्यों को बढ़ाने वाले को शामिल करने की जरूरत प्रकट करने का विशेषाधिकार क्या सिर्फ केसरिया ब्रिगेड को है। उन्होंने इस सन्दर्भ में फरवरी 1999 में संसद में पेश एक रिपोर्ट का जिक्र किया। रिपोर्ट "कांग्रेसी" एस.बी. चव्हाण ने पेश की थी। मूल्य आधारित शिक्षा पर सुझाव देने के लिए गठित समिति के रूप में भी चव्हाण द्वारा पेश इस रिपोर्ट के एक अंश को उद्धृत करते हुए श्री राजपूत ने इस बार नये पाठ्यक्रम में मूल्यों के समावेश को जायज ठहराया। उद्धृत अंश इस प्रकार है : "समिति सामाजिक साहचर्य और सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द के एक उपकरण के रूप में धर्मों के बारे में शिक्षा देने की जोरदार हिमायत करती है।" इसके साथ ही श्री राजपूत ने घलुए में एक और सफाई जोड़ दी कि छात्रों को "धार्मिक शिक्षा" नहीं दी जायेगी। धार्मिक के साथ-साथ सामाजिक एवं संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जायेगी।

सनद रहे कि समाज में मूल्यों के ह्रास पर चिन्तित होने के केसरिया ब्रिगेड" के विशेषाधिकार को चुनौती देकर प्रो. राजपूत ने एक साहसिक कार्य किया है। बहुत-बहुत बधाई। अपने जनतांत्रिक अधिकार को केसरिया ब्रिगेड के हमलों से कितनी चपलता से आपने बचा लिया। आपने बड़ी कुशलता से यह भी साबित कर दिया कि समाज में मूल्यों के ह्रास के प्रश्न पर "कांग्रेसी" एस.बी.चव्हाण और केसरिया दुपट्टाधारी जोशी जी के चिन्तन और चिन्ताओं में कितनी समानता है। लेकिन इस पैंतरेबाजी के बावजूद आप अपने को बेदाग नहीं ठहरा सकें है प्रो. राजपूत!

प्रो. राजपूत, आपकी चिन्ता के असली-नकली होने के विवाद में पड़े बिना यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आपका चिन्तन न तो वैज्ञानिक है और न व्यावहारिक। मौलिकता के प्रति आपका कोई आग्रह नहीं है। आपने यह ईमानदारी भी बहादुरी के साथ दिखायी है। एस.बी. चव्हाण के साथ-साथ आप अमरीकियों से भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आपके ही अनुसार द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमरीकियों ने भी जब मूल्य-आधारित शिक्षा व्यवस्था की ओर देखना शुरू किया तो फिर हम क्यों पीछे रहें (देखें स्टेटसमैन, 14 दिसम्बर, 2000)। (अमरीकियों से प्रेरणा ग्रहण करने के मामले में आप केसरिया बिग्रेड को चुनौती नहीं दे सकें, इसका अफसोस रहेगा।)

लेकिन शिक्षा में मूल्यों के समावेश पर चिन्तन करते हुए आपने यदि वैज्ञानिक पद्धति का समावेश किया होता तो शायद आप मूल्यों के ह्रास की समस्या की तह तक पहुंच सकते थे। यदि समाज की एक छोटी से विशेषाधिकार प्राप्त आबादी बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी के श्रम को निचोड़कर उन्हें जीवन के अधिकार से वंचित करती रहेगी तो ऐसे में आप मूल्यों का कौन सा पाठ पढ़ायेंगे? क्या मूल्य हवा में पैदा होते हैं या आसमान से आ टपकते हैं? क्या आप उन्हें "फल की चिन्ता किये बना कर्म किये जा" का पाठ पढ़ायेंगे या 'सन्तोषं परमं सुखम' का। क्या नयी पीढ़ी के सामने इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया, फिल्मों व अन्य माध्यमों से बाजार आधारित मूल्यों की चौबीसों घंटे दी जा रही भारी खुराकों का मुकाबला स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल आपके नये इंजेक्शन कर पायेंगे। क्या जब नयी पीढ़ी की आंखों के सामने आदर्श चरित्र नायक-नायिकाओं के रूप में हर्षद मेहताओं, अमिताभ बच्चनों, हृतिक रोशनों, सचिन तेंदुलकरों, सुष्मिता सेनों, ऐश्वर्य रायों, प्रियंका चोपड़ाओं जैसी विभूतियां मौजूद हों तो पौराणिक कथाओं के नायकों—अवतारी पुरुषों की जीवन लीलाएं उन्हें सच्चरित्र व आदर्शवान बनने को कैसे प्रेरित कर सकेंगी? क्या इस बाजारू चकाचौंध में उनके अन्दर "तामसी" और "राजसी" गुणों के प्रति वितृष्णा का भाव और "सात्विक" गुणों के प्रति एकात्म निष्ठा का भाव पैदा किया जा सकता है? समाज में "पड़ोसी की जलन आपकी शान" वाली हिंसक ईर्ष्यालु भावना भी राज करे और "देख परायी चुपड़ी मत ललचाये जी" का आदर्श भी फले-फूले, यह साथ-साथ कैसे होगा? इस असंगति को कैसे मिटायेंगे आप प्रो. राजपूत?

"रामलला हम आयेंगे, मन्दिर वहीं बनायेंगे", "जिस हिन्दू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है", जैसे आक्रामक नारों के शोर और "मनुवाद" के विरोधियों और समर्थकों के बीच छिड़ी "सामाजिक न्याय की जंग" के बीच "धार्मिक सौहार्द" का भाव कैसे पैदा कर सकेंगे? स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में मूल्यों का समावेश करने के इरादे रखने वाले महानुभावों को आज के आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक

(शेष पृष्ठ 10 पर)

(पृष्ठ 8 का शेष)

परिवेश की ये विसंगतिया नजर नहीं आयी होंगी, ऐसा नहीं है। बात दरअसल यह है कि नैतिकता और मूल्यों के बारे में चिन्तित ये सज्जन खुद भी समाज की इन्हीं विसंगतियों की उपज हैं। प्रो. राजपूत जैसे लोगों का चिन्तन उस चौहद्दी के बाहर जा ही नहीं सकता जहां से बाहर निकलकर ही इन विसंगतियों को सुलझाया जा सकता है। वह चौहद्दी है लूट एवं शोषण पर टिकी आज के समाज की आर्थिक बुनियाद व इस पर खड़ी हुई समूची राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक इमारत, जिसे ध्वस्त किये बिना शिक्षा के ढांचे में किसी मूलभूत बदलाव की बात करना या तो काइयांपन हो सकता है या निरी मूर्खता। प्रो. राजपूत किस कोटि के हैं यह आकलन करना महत्वहीन है।

हां, प्रो. राजपूत एक दुविधा के शिकार जरूर हैं, जिसे व्यक्त करते समय वे नये पाठ्यक्रम की व्यावहारिकता पर खुद ही सवाल कर बैठते हैं। वह कहते हैं कि नये पाठ्यक्रम के जरिये सिखाये जाने वाले मूल्य प्रभावी होंगे या नहीं यह बच्चे के बाह्य परिवेश पर निर्भर करता है। लेकिन, इस बात से सिखाये जाने वाले मूल्यों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसलिए किसी स्तर पर इनका पाठ नहीं पढ़ाया जाये, इसे जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। इस पर तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि प्रो. राजपूत आप पूरे मनोयोग के साथ फल की चिन्ता किये बिना कर्म करते जाइये, दुविधा में पड़ेंगे तो न माया मिलेगी न राम मिलेंगे, न मुरलीधर। ●

(पृष्ठ 9 का शेष)

व्याख्या या कोई विधि वर्णित नहीं है। लेकिन, "भूमण्डलीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मददगार" शिक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से इसकी संक्षिप्त व्याख्या ऐसे की जा सकती है :

पहला, विशिष्ट वर्ग के उन छात्रों का ई. क्यू और एस.क्यू उच्चस्तरीय होगा जो कम्प्यूटर-इंटरनेट की उच्च तकनीकी शिक्षा पूर्ण एकाग्रचित्त होकर अर्जित करेंगे और हर प्रकार के सामाजिक अन्याय, असमानता और शोषण से मुंह फेरकर पूर्णतया भावनाहीन और संवेदनहीन बनने को तत्पर होंगे। दूसरा, सामान्य वर्ग के उन छात्रों का एस. क्यू और ई. क्यू उच्च स्तरीय होगा जो राजभक्त और स्वामिभक्त होंगे, प्रभु वर्ग की सेवा अपनी नियति या पुराने पापों का फल मानकर करते रहेंगे और देशी-विदेशी लुटेरों की भूमंडलीय व्यवस्था की जड़ खोदने की दिशा में दिमाग को भटकने से रोकेंगे। ●

शिक्षा को उम्दा बाजारू माल बनाने के लिए बिड़ला-अम्बानी कम्पनी का नया फार्मूला

आदेश सिंह

बिड़ला और अम्बानी समूह को आप किस रूप में जानते हैं? विभिन्न किस्म के औद्योगिक उत्पादों के जरिये भारत के घरेलू बाजार को अपने कब्जे में रखने वाली एकाधिकारी पूंजी के स्वामियों के रूप में ही अगर अब तक आप जानते हैं तो आपकी जानकारी बासी पड़ चुकी है। कृपया ताजा जानकारी से अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा लें। बिड़ला-अम्बानी की ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी ने शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता के लिए एक नये उत्पाद का फार्मूला पास करने के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा है। इस बात की सम्भावना शून्य के बराबर है कि फार्मूला रिजेक्ट कर दिया जाये।

शायद आपकी जानकारी में यह बात न हो कि शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में बिड़ला-अम्बानी कम्पनी को मान्यता स्वयं प्रधानमंत्री ने ही दी थी। प्रधानमंत्री के विशेष निर्देश पर विगत 28 अगस्त 1998 को एक अधिसूचना जारी कर व्यापार एवं उद्योग परिषद का गठन किया गया था। उस समय इसके सदस्य थे—रतन टाटा, कुमारमंगलम बिड़ला, मुकेश अम्बानी, आर.पी. गोयनका, पी.के. मित्तल, सुरेश कृष्ण (टी.वी. एस.ग्रुप), एन.आर.नारायणमूर्ति (इनफोसिस वाले), नुस्ली वाडिया, ए.सी. मुथैया और डॉ. परविन्दर सिंह। परिषद के अध्यक्ष स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी थे। 13 नवम्बर 1999 को एक अन्य अधिसूचना के जरिये इसका पुनर्गठन किया गया, जिसके जरिये सदस्यों में कुछ बदलाव कर संजीव गोयनका, राहुल बजाज, एन. श्रीनिवासन, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव बृजेश मिश्रा को शामिल किया गया। इस परिषद के तहत छह ग्रुप बनाये गये जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा क्षेत्र, पूंजी बाजार, निजीकरण, अच्छा शासन आदि पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके लिए उन्हें सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय से अधिकतम सम्भव सहयोग और सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया। 11 दिसम्बर 1999 को फिर इन छह ग्रुपों को बढ़ाकर आठ कर दिया गया और उनसे सलाह मांगी गयी। मुकेश अम्बानी और कुमारमंगलम बिड़ला शिक्षा के लिए गठित विशेष समूह के विशेषज्ञ बनाये गये।

इन धनकुबेर विशेषज्ञों ने भूमण्डलीकरण चश्मे और अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष-विश्वबैंक के 'स्टेथोस्कोप' से देश की उच्च शिक्षा की बीमारी का अध्ययन कर इलाज के लिए नुस्खे तैयार किये और "दवा का सैम्पल" जनवरी महीने में प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया है। सम्भावना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने में कोई अड़चन नहीं आयेगी और दवा को व्यापक स्तर पर उपभोग के लिए बाजार में जल्दी ही उतारा जायेगा।

हालांकि जो सिफारिशें भेजी गयी हैं, वे नयी नहीं हैं क्योंकि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में सीमित पैमाने पर इनका अमल पहले से ही जारी है। कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- एक निजी विश्वविद्यालय-विधेयक तैयार किया जाये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करे।
- विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली सरकारी सहायता धीरे-धीरे खत्म कर दी जाये।
- शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उपाय किये जायें।
- कानून बनाकर विश्वविद्यालयों-कालेजों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी जाये।
- प्राइवेट रेटिंग कम्पनियों से विश्वविद्यालयों के काम-काज की रेटिंग करवाई जाये।

ये सभी सिफारिशें भूमण्डलीकरण के मौजूदा दौर में देशी-विदेशी पूंजी की नयी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के आदेशपत्र जैसे हैं जिन्हें अमली जामा पहनाने के लिए अब सिर्फ सरकारी मुहर की जरूरत बाकी है। शिक्षा क्षेत्र को देशी-विदेशी पूंजी के निवेश के लिए तैयार करने के लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा के बारे में "परम्परागत" सोच को बदला जाये। शिक्षा को अन्य उद्योगों जैसा दर्जा दिया जाये जिसमें सिर्फ लाभ-हानि के गणित पर पूंजीप्रवाह हो। शिक्षा के बारे में सोच बदलने का काम पिछले एक दशक से जारी है। भाड़े के शिक्षाविद, बाजारप्रेमी प्रोफेसर और मीडिया के कलमघिस्सू पश्चिमी देशों के उदाहरण दे-देकर इस काम में अपनी सारी ऊर्जा लगाये हुए हैं। एक मानसिकता तैयार की जा रही है कि शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व और समाज का विषय